संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष









भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

26th February, 2024

DO No. 09/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

In the profound wisdom of ancient Indian texts, the pursuit of dharma, or righteous duty, has been emphasized as the guiding principle for individuals from various walks of life. The concept of "Loka Sangraha", from the sacred scripture -Bhagavad Gita, resonates with contemporary relevance. Mahatma Gandhi linked loka sangraha with the concept of sacrifice (or "yajna") to highlight that one must sacrifice oneself for the sake of the greater good. Therefore, loka sangraha encourages public servants to work for the welfare of the people at large. For the officers of CBIC, this timeless philosophy underscores the imperative of ethical conduct and efficient administration in the realm of trade and commerce. Drawing inspiration from the Bhagavad Gita, where Lord Krishna imparts the importance of selfless action, we, as officers, are reminded that our responsibilities extend beyond mere bureaucratic tasks. In our context, the concept of loka sangraha implies creating an environment conducive to trade, where businesses can thrive, and taxpayers can enjoy the fruits of a fair and just taxation regime. By aligning our actions with the principles of dharma and loka sangraha, we become the champions of ethical and efficient administration and fulfil the higher purpose of serving the greater good and upholding the values embedded in ancient Indian wisdom.

Coming to last week's important update, I would like to mention that Indian Customs and Singapore Customs virtually signed the Joint Action Plan for phased negotiations of the Authorized Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AEO-MRA). This arrangement is aimed at enhancing supply chain security and trade facilitation between India and Singapore. The signing of the Joint Action Plan signifies a commitment to mutual recognition of Authorized Economic Operators between the two countries.

With regards GSTN Back Office (BO) training of CBIC officers, NACIN Faridabad commenced training of the first batch of master trainers in December last year in close coordination with GSTN Team. I have been informed that 552 officers from 108 CGST Commissionerates have been trained as master trainers in 11 Batches altogether. I expect that the CGST Zones will make earnest efforts to

take up the training of remaining workforce of CBIC with the help of these Master trainers so as to ensure smooth transition to the GSTN BO within the scheduled timelines.

In an interesting case booked by the Directorate General of GST Intelligence, Lucknow Zonal Unit, the officers gathered that three Agra-based taxpayers were availing fake Input Tax Credit (ITC) on the raw materials allegedly for manufacturing of 'Handpumps'. The fake ITC on raw materials (@18%) was further used to issue fake invoices of handpumps (@5%) to non-existent entities without any actual manufacture and supply. Adopting this modus, the taxpayers were obtaining fraudulent refunds under an "inverted duty structure" with evasion amounting to Rs. 15.27 Crore so far. The mastermind of the whole operation, who has been placed under judicial custody, accepted the fraud committed and voluntarily deposited Rs. 5.21 Crore.

Till next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष









भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

26 फरवरी, 2024

DO No. 09/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी,

प्राचीन भारतीय ग्रंथों के गहन ज्ञान में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक सिदधांत के रूप में धार्मिक या न्याय परायण कर्तव्य की खोज पर जोर दिया गया है। पवित्र ग्रंथ - भगवदगीता से "लोक संग्रह" की अवधारणा, समकालीन प्रासंगिकता के साथ प्रतिध्वनित होती है। महात्मा गांधी ने लोक संग्रह को बलिदान (या "यज्ञ") की अवधारणा से जोड़ा, ताकि इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि अधिक से अधिक भलाई के लिए व्यक्ति को स्वयं का बलिदान देना चाहिए। इसलिए, लोक संग्रह लोक सेवकों को बडे पैमाने पर लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीबीआईसी के अधिकारियों के लिए, यह कालातीत दर्शन व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में नैतिक आचरण और क्शल प्रशासन की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। भगवदगीता से प्रेरणा लेते हुए, जहां भगवान कृष्ण निस्वार्थ कार्रकर्म के महत्व को बताते हैं, हमें, अधिकारियों के रूप में, याद दिलाया जाता है कि हमारी जिम्मेदारियां महज नौकरशाही कार्यों से परे हैं। हमारे संदर्भ में, लोक संग्रह की अवधारणा का तात्पर्य व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, जहां व्यवसाय फल-फूल सकें, और करदाता निष्पक्ष और उचित कराधान व्यवस्था का लाभ उठा सकें। अपने कार्यों को धर्म और लोक संग्रह के सिद्धांतों के साथ जोड़कर, हम नैतिक और कुशल प्रशासन के समर्थक बन जाते हैं और व्यापक भलाई करने और प्राचीन भारतीय ज्ञान में अंतर्निहित मूल्यों को बनाए रखने के उच्च उददेश्य को पूरा करते हैं।

पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर आते हुए, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय सीमा शुल्क और सिंगापुर सीमा शुल्क ने Authorized Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AEO-MRA) की चरणबद्ध वार्ता के लिए संयुक्त कार्य योजना (Joint Action Plan) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच आपूर्ति शृंखला सुरक्षा और व्यापार सुविधा को बढ़ाना है। संयुक्त कार्य

योजना (Joint Action Plan) पर हस्ताक्षर करना दोनों देशों के बीच Authorized Economic Operator की पारस्परिक मान्यता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

सीबीआईसी अधिकारियों के GSTN Back Office (BO) प्रशिक्षण के संबंध में, NACIN फरीदाबाद ने जीएसटीएन टीम के साथ समन्वय में पिछले साल दिसंबर में मास्टर प्रशिक्षकों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू किया। मुझे बताया गया है कि 108 सीजीएसटी आयुक्तालयों के 552 अधिकारियों को कुल मिलाकर 11 बैचों में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि सीजीएसटी जोन इन मास्टर प्रशिक्षकों की मदद से सीबीआईसी के शेष कार्यबल के प्रशिक्षण के लिए तत्परता प्रयास करेंगे ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर GSTN BO की ओर परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

जीएसटी असूचना महानिदेशालय, लखनऊ जोनल यूनिट द्वारा दर्ज एक दिलचस्प मामले में, अधिकारियों ने पाया कि आगरा स्थित तीन करदाता कथित तौर पर 'हैंडपंप' के निर्माण के लिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ले रहे थे। इनपुट पर नकली आईटीसी (@18%) का उपयोग बिना किसी वास्तविक निर्माण तथा आपूर्ति के गैर-मौजूद संस्थाओं को हैंडपंप (@5%) के नकली चालान जारी करने के लिए किया गया था। इस पद्धति को अपनाकर, करदाता "Inverted Duty Structure" के तहत रिफंड के माध्यम से अब तक 15.27 करोड़ रु. रुपये की कर चोरी कर चुके है। पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड, जिसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है, ने धोखाधड़ी स्वीकार कर स्वेच्छा से 5.21 करोड़ रुपये जमा कर दिए है।

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

क्रियम कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण ।